नव भारत
1934 से
इंदौर 65 वां वर्ष संस्करण

प्राकृतिक खेती है जीवन जीने की पद्धति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास के उस मार्ग पर अग्रसर है, जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समान महत्व दिया जा रहा है। इसी समग्र दृष्टि के अंतर्गत भारतीय कृषि को भी एक नए युग की ओर ले जाया जा रहा है। कृषि सदियों से हमारी सभ्यता की रीढ़ रही है। आधुनिक युग में रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता ने खेती की लागत बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता, उसकी जलधारण क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, हमारे भोजन की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी परंपराओं और ज्ञान प्रणाली में निहित है। इसी विचार से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जो भारतीय कृषि की मूल आत्मा से जुड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।

भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था सह-अस्तित्व और संतुलन पर आधारित रही है, जिसमें गौमाता की भूमिका केंद्रीय रही है। गौ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा का आधार रही हैं। 'सहकारिता से समृद्धि' के तहत, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को संगठित किया जा रहा है एवं किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि छोटे किसानों को न केवल सस्ती दरों पर प्राकृतिक खाद-बीज मिल सकें बल्कि उनके विषमुक्त उत्पादों को उचित बाजार और लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो सके।

प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भर बनेगा भारत

प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि में प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की भारतीय पद्धति है। वे इसे किसानों की लागत घटाने, आय बढ़ाने और उन्हें बाहरी निर्भरता से मुक्त करने का सशक्त माध्यम मानते हैं। साथ ही, यह देशवासियों को रसायन-मुक्त, विषरहित भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग है। यही कारण है कि प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है। प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली सरल, स्वदेशी और प्रभावशाली है। इसमें गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि कृषि आदानों के उत्पादन के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य जैसे प्राकृतिक इनपुट मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं और भूमि की उर्वरता को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाते हैं।

किसान कल्याण

वर्ष 2026 समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश

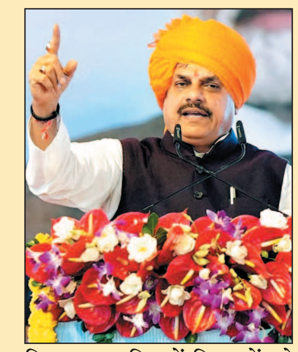

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि का क्षेत्र गरीब वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला मुख्य क्षेत्र है। कृषि से संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वावलंबन के भी कई अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की पर्याप्त संभावना है। प्रदेश की विविधता से परिपूर्ण भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खेती से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जाएगी। धान की खेती को प्राथमिकता देने के साथ गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, हॉर्टीकल्चर आदि के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों के साथ ही अन्य देशों में हो रहे नवाचारों से अवगत कराने के लिए कृषकों को विविध देशों का भ्रमण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की टैगलाइन के साथ कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहेगा। किसानों की आय दोगुनी करने से आगे बढ़कर कृषि को लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक प्रेरित, रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना कृषि वर्ष का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि वर्ष का मासिक कैलेंडर तैयार किया गया, जिसमें किसानों को साथ लेकर राज्य से जिला स्तर तक महोत्सव, मेले आदि की रूपरेखा बनी। आत्मनिर्भर किसान, उन्नत कृषि और कृषकों के हित में बाजार से संबंधों के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से समृद्ध प्रदेश के निर्माण के विजन से गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

प्रमुख बिन्दु

- कृषि से संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वावलंबन के भी कई अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहेगा।
- प्रदेश की विविधता से परिपूर्ण भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खेती से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जाए।
- नवाचारों से अवगत कराने के लिए कृषकों को विविध देशों का भ्रमण कराया जाए।
- किसानों की आय दोगुनी करने से आगे बढ़कर कृषि को लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक
- प्रेरित , रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना कृषि वर्ष का मूल उद्देश्य है।

कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत राज्य में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम

जनवरी-2026
- नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केन्द्रों का राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन तथा सोयाबीन के साथ मूंगफली और सरसों को योजना में शामिल करने के लिए भावांतर योजना विस्तार कार्यक्रम।
- भोपाल में गुलाब महोत्सव का आयोजन-पुष्प उत्पादक, निर्यातक और विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे।

फरवरी-2026
- उज्जैन में गुलाब महोत्सव।
- भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम।
- ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुधन और अन्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में नवीन संभावनाओं पर कृषि मंथन और कृषि मेले का आयोजन।

मार्च-2026
- प्राकृतिक खेती पर भोपाल में राष्ट्रीय संगोष्ठी, राज्य स्तरीय ट्रेड फेयर तथा बायर-सेलर मीट। संभाग स्तर पर भी प्राकृतिक खेती पर प्रदर्शनियां और सेमिनार होंगे।
- ग्वालियर में दुग्ध उत्पादकों का सम्मेलन। प्रत्येक दुग्ध संघ स्तर पर भी दुग्ध उत्पादकों का सम्मेलन होगा।
- इंदौर में पशुपालन पर कार्यक्रम।

अप्रैल-2026
- जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम।

मई-2026
- सिवनी में धान महोत्सव तथा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- इंदौर/जबलपुर में कुक्कुट पालकों व उद्यमियों का सम्मेलन।
- इंदौर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम।

जून-2026
- भोपाल में राज्य स्तरीय आम महोत्सव।
- उज्जैन में राज्य स्तरीय कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला।
- सागर में राज्य स्तरीय सोया महोत्सव तथा किसान सम्मेलन। इंदौर, उज्जैन और विदिशा में भी संभागीय आयोजन होंगे।
- जबलपुर में राज्य स्तरीय सिंघाड़ा और मखाना महोत्सव।

जुलाई-2026
- नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास एवं कस्टम हायरिंग राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर कार्यक्रम।
- नर्मदापुरम में सिंघाड़ा और मखाना महोत्सव।

अगस्त-2026
- बैतूल में जिला स्तरीय आम महोत्सव।
- इंदौर में राज्य स्तरीय एफपीओ सम्मेलन। इसमें नवीन तकनीकों के ज्ञान, अवलोकन, विचार-विमर्श तथा प्रदर्शनी और विशेषज्ञों के विचारों को साझा करना शामिल होगा।
- बैतूल में जिला स्तरीय आम महोत्सव।
- भोपाल में राज्य स्तरीय केन्द्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण। इसका उद्देश्य मिलावटी दुग्ध व दुग्ध उत्पादों पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।

सितम्बर-2026
- छिंदवाड़ा में कृषि अवसंरचना निधि योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला।
- उज्जैन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं और पशुपालकों का सम्मान।

अक्टूबर-2026
- भोपाल में पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन पर कार्यशाला। जिला स्तर पर भी होंगे सम्मेलन।
- इंदौर में जलीय कृषि विपणन संगोष्ठी।
- इंदौर में राज्य स्तरीय सब्जी महोत्सव। जिला स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम।

नवम्बर-2026
- राजगढ़ में जिला स्तरीय सब्जी महोत्सव।
- भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन। डिजीटल समावेशन और कृषकों की सदस्यता का विस्तार होगा लक्ष्य। जिला स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम।
- मंडी आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप साफ, ग्रेडेड और पैक्ड उपज से प्रदेश के कृषि उत्पादों की राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी भागीदारी

एक नजर में

सिंहस्थ 2028 के आयोजन हेतु क्षिप्रा नदी को निर्मल-अविरल एवं निरंतर प्रवहमान बनाकर श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विभिन्न धार्मिक पर्वो पर अनुष्ठान हेतु पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने के लिये विभाग द्वारा विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं।

- उज्जैन जिले की कान्ह नदी पर कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना (क्षिप्रा शुद्धिकरण)
- उज्जैन जिले की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना (नदी एवं जल निकायों का विकास)
- क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 30 किलोमीटर घाट निर्माण
- क्षिप्रा नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा 09 बैराज का निर्माण (उज्जैन जिले में 01, इंदौर जिले में 01 एवं देवास जिले में 07 बैराज) एवं नगर निगम उज्जैन द्वारा कालियादेह स्टॉप डेम का मरम्मत कार्य।
- कान्ह नदी पर 11 बैराजों (उज्जैन जिले में 05 एवं इंदौर जिले में 06) का निर्माण कार्य।
- केन-बेतवा राष्ट्रीय परियोजना
- पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय परियोजना
- मेगा तापी रीचार्ज परियोजना
- डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल
- अटल भू-जल योजना
- जल गंगा संवर्धन अभियान
- दौधन बाँध का निर्माण कार्य प्रारंभ ।
- कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना (मंदसौर)
- बंडा परियोजना यूनिट 2 (सागर और छतरपुर)
- रामपुरा-मनासा सिंचाई परियोजना (नीमच)
- सुठालिया सिंचाई परियोजना (राजगढ़)
- पार्वती परियोजना (राजगढ़, भोपाल एवं सीहोर)
- मल्हारगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (मंदसौर)
- त्यौंथर बहाव योजना (रीवा)
- हनौता सिंचाई परियोजना (सागर एवं विदिशा)
- रिहन्द सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सिंगरौली)

प्रदेश में गत दो वर्षों में सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसानों की खुशहाली की परिकल्पना को साकार करते हुए मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रदेश को दी गई तीन बड़ी परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक करने में सफलता मिलेगी। प्रदेश में गत दो वर्षों में सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। किसानों की तरक्की और खुशहाली हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि के अतिरिक्त पेयजल, उद्योगों, विद्युत उत्पादन आदि के लिए जल की उपलब्धता कराये जाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। बीते 2 वर्षों में हरदा, बड़वानी और धार जिलों के जनजातीय अंचलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई उपलब्ध कराने वाली परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

केन-बेतवा राष्ट्रीय परियोजना

परियोजना की लागत 44 हजार 605 करोड़ रूपये है। इससे सिंचाई 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में हो सकेगी। परियोजना से बुन्देलखण्ड के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ, निवाडी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर के लगभग 2 हजार ग्रामों के 7 लाख 25 हजार किसान परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही 44 लाख आबादी को पेयजल मुहैया हो सकेगा।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय परियोजना

परियोजना से मालवा एवं चंबल क्षेत्र के 13 जिले गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, देवास, इंदौर, आगर मालवा, शाजापुर, श्योपुर, ग्वालियर एवं भिण्ड में 6.16 लाख हेक्टेयर में नवीन सिंचाई एवं चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर के 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हो सकेगी। लगभग 2 हजार 94 ग्रामों की 40 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

प्रदेश के अन्नदाता अब बनेंगे ऊर्जादाता

किसान करेंगे सूरज से खेती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में किये जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों से प्रदेश में अन्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों को खेती के लिये खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे है। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में 52 हजार किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गई है। सोलर पंप स्थापित हो जाने से अब प्रदेश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेगा। अब प्रदेश के किसान सूरज से खेती करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस अभिनव पहल के तहत 34 हजार 600 इकाइयों को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर 33 हजार कार्यदेश जारी किए जा चुके हैं। किसान के खेत में सोलर पम्प स्थापित होने से अब उन्हें विद्युत प्रदाय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बिजली बिल पर व्यय होने वाली यह राशि अब उनके पास बचत के रूप में रहेगी। इसके अतिरिक्त सोलर पम्प से उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को किसान सरकार को बेच कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा लगातार किसानों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं में लाभ प्रदान कर सक्षम बनाया जा रहा है।

52 हजार किसानों के खेत अब लहलहाएंगे सोलर पम्प से

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 52 हजार किसानों के खेतों में सोलर पम्प लगाने का अभिनव नवाचार किया है। योजना में मंदसौर, नीमच, बैतूल,भिंड, सागर, शाजापुर, जबलपुर, अशोकनगर, भोपाल एवं सीहोर जिलों में कृषकों के यहाँ सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

भावांतर योजना

सोयाबीन किसानों का सुरक्षा कवच

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि भावांतर, केवल एक योजना नहीं किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धाभाव है। भावांतर की राशि किसानों के अधिकार की राशि है। यह राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। नए वर्ष 2026 को सरकार ने अन्नदाताओं के कल्याण को ही समर्पित किया है। इस वर्ष हम कृषि उत्सव मनाएंगे। किसान भाइयों की समृद्धि का उल्लास मनाएंगे। आधुनिक तरीके से खेती, कृषि विस्तार सेवाएं और नई-नई तकनीकों को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, जिससे किसान भाई अपनी खेती-किसानी को और बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही निर्णय ले सकें। अन्नदाताओं के कल्याण को ही समर्पित किया है।

अब तक प्रदेश के 6.25 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान कर चुकी है। भावांतर योजना प्रदेश के किसानों का सुरक्षा कवच बन गई है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार की प्राईस सर्पोट स्कीम अंतर्गत सोयाबीन का उपार्जन किया गया.

मध्यप्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम

किसानों के हर सुख-दुख में साथ है मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि विकास और किसान कल्याण में मध्यप्रदेश सरकार प्राण-प्रण से जुटी हुई है। मध्यप्रदेश उत्पादक गतिविधियों में नवाचार कर रहा है। सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है। प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उत्पादन में रिकार्ड दर्ज कर प्रदेश को अनेक अवार्ड हासिल हुए हैं। म.प्र. दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, खाद्यान उत्पादन में द्वितीय स्थान पर और तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। प्रदेश में त्रि-फसली क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार द्वारा रबी 2024-25 में उपार्जित गेहूँ पर राशि रूपये 175 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई।

कस्टम हायरिंग केन्द्र

कृषकों को सस्ते दर पर यंत्र उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाये जाने के लिये सरकार के संकल्प के अनुसार हर वर्ष 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। अब तक 4730 कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश स्तर पर स्थापित है जिससे कृषकों को लाभ मिल रहा है। कस्टम हायरिंग के 25 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट पर 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है।

जल संरक्षण | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया 'स्वच्छ जल अभियान' का आगाज

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता का होगा व्यापक परीक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रांत व्यापी 'स्वच्छ जल अभियान' का हुआ। यह अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ शुरू किया गया है। अभियान में नगरीय निकायों एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायत एवं ग्रामीण, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य एवं जिला के अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनाए गए हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता का व्यापक परीक्षण करना है। साथ ही जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज, दूषित जल की पहचान कर समय पर सुधार करना, जिससे जल-जनित बीमारियों से बचाव हो सके। स्वच्छ जल के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित और जांच प्रक्रिया में सहभागिता के लिए जागरूक करना, जिससे आमजन स्वयं ही पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दें और समय रहते प्रशासन को अवगत करा सकें। प्रदेश में अभियान का संचालन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। अभियान का दूसरा चरण एक मार्च से प्रारंभ होकर 31 मई तक चलेगा।

जल सुरक्षा

- पानी की सेम्पलिंग एवं टेस्टिंग।
- समस्त हैंडपंप तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्रोतों का सेनेटरी सर्वेक्षण करना।
- समस्त क्रियाशील हैंडपंपों तथा नलजल योजना के स्रोतों का डिसइंफेक्शन करना।
- खुले कुओं में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ब्लीचिंग पाउडर डालकर डिसइंफेक्शन कराना।
- समस्त टंकियों की सफाई।

जल संरक्षण

- सुधारात्मक कार्यवाही-लीकेज को चिन्हित कर दुरुस्त करना।
- पाइप लाइन के आस-पास ट्रैवर्स कर लीकेज की पहचान करना।
- साधारण मरम्मत के कार्य (माइनर रिपेयर वोल्व एवं जॉइंट्स)
- जल वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
- जल भंडारण एवं जलाशय प्रबंधन।

जल सुनवाई

- समस्त निकायों में हेल्पलाइन नंबर (181) उपलब्ध कराना।
- हर मंगलवार की जिलावार जनसुनवाई में नागरिक जल सम्बंधित शिकायतें ले जा सकते हैं जिसकी त्वरित सुनवाई की जाएगी।
- यदि नागरिक जनसुनवाई में दूषित जल सैंपल लेकर आते हैं, तो उसके टेस्ट रिजल्ट 48 घाटे में बता दिए जाएंगे।

इम्पैक्ट फीचर/D-16140/25